ISSN 0973-8541, HUMANITIES AND DEVELOPMENT, VOL.20, No.1, Jan. – Mar., 2025/7

उच्च शिक्षित छात्राओं के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 : एक समाजशास्त्रीय दृष्टि

सुनीता पाण्डेय एवं योगेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी,
https://doi.org/ 10.61410/ had.v20i1.220

परिचय –

भारतीय समाज में उच्च शिक्षा के संदर्भ में छात्राओं अथवा महिलाओं की स्थिति कभी भी एक समान नहीं रही। दूसरे शब्दों में इनमें कभी भी एक समान निरंतर नहीं रही। किसी समय काल में भारतीय महिलाएं पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त एवं शिक्षित रही तो अन्य युगों में उसे योजनाबद्ध तरीके से उच्च शिक्षा से वंचित रखते हुए घर की चार – दीवारी में सीमित कर दिया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 एवं नवीन शिक्षा नीति 1986 के पश्चात भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया। शिक्षा नीति को मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत चलाया गया था लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद इस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। यह नीति उच्च शिक्षा को अपनी भाषा में पढ़ने की स्वतंत्रता देने के साथ ही बच्चों को कला और खेलकूद के क्षेत्र में बढ़ावा देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र–छात्राओं को सुविधानुसार एवं समय की उपलब्धतानुसार शिक्षा प्राप्त करने की विशेष प्रावधान हैं। इससे महिला शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रावधान के अंतर्गत समयाभाव अथवा पढ़ाई बीच में छूट जाने पर भी इसे संपूर्णता प्रदान करने का प्रावधान महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात स्नातक करते–करते वयस्क होने की अवस्था में कई छात्राओं का विवाह कर दिया जाता है। ऐसी स्त्री में छात्राओं का अध्ययन कई अवसरों पर बीच में ही छूट जाता है अर्थात कई छात्राओं को परिस्थितिवश कॉलेज शिक्षा बीच में ही छोड़नी होती है। जहां पूर्व शिक्षा नीति अनुसार स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पूर्ण नहीं करने की स्थिति में किसी प्रकार का डिप्लोमा अथवा डिग्री प्राप्त नहीं होती थी, वहीं अब इस प्रकार की छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर यह होता है कि यदि कोई छात्रा कॉलेज में पहले वर्ष की पढ़ाई पूर्ण करती हैं तो उसे सर्टिफिकेट दूसरे वर्ष पर डिप्लोमा व तीसरे और चौथे वर्ष में डिग्री दी जाती है। वैसे तो यह नीति सभी के लिए उपयोगी है पर यह छात्राओं के लिए विशेष उपयोगी है। नई शिक्षा नीति में लिंग – समावेशी कोर्स की स्थापना एक ऐतिहासिक पहल है। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार छात्रावासों तक सुरक्षित और व्यावहारिक पहुंच प्रदान की जाती है। जहां शिक्षण संस्थान निवास स्थान से अधिक दूरी ग्रामीण अंचलों, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों, दूर – दराज के इलाकों में स्थित है वहां छात्राओं के लिए छात्रावासों की निशुल्क व्यवस्था की भी व्यवस्था की गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। नई शिक्षा नीति 2020 में पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, का स्थान ले लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा के साथ–साथ ग्रामीण और शहरी भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य जल्द ही पुरानी भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है, और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, धर्म, लिंग, जाति या पंथ के किसी भी भेदभाव के बिना सभी को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर प्रदान करने एवं स्वयं का विकास करने के लिए एक समान मंच प्रदान करना है। साथ ही साथ सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके मौजूदा जीवंत ज्ञान समाज को बनाए रखना और उसकी देखभाल करना है। यह

शोध छात्रा– समाजशास्त्र विभाग, डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
आचार्य – समाजशास्त्र विभाग, का0सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या।

भारत को पुनः वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने की दिशा में भी एक कदम है। इस नीति में यह परिकल्पना की गई है कि हमारे शिक्षा संस्थाओं में समान पाठ्यक्रम के माध्यम से अध्यनरत सभी छात्रों एवं छात्राओं में समाज के प्रति सम्मान की भावना पैदा करनी चाहिए एवं सामाजिक मूल्यों के प्रति तथा अपने देश और एक बदलती दुनिया के साथ एक निश्चित सामाजिक संबंध स्थापित करना चाहिए। इस नीति का दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच ज्ञान, कौशल, आत्मविश्वास, बुद्धि और कर्म के साथ न केवल विचार बल्कि मूल्यों और दृष्टिकोण में भी विकास करना है, जो मानव अधिकारों के सतत विकास और जीवन का समर्थन करते हैं। साथ ही साथ वैश्विक कल्याण के लिए एक जिम्मेदार प्रतिबद्धता, जिससे वास्तव में एक वैश्विक नागरिक प्रतिबिंबित होता है ऐसी सामाजिक मूल्यों को स्थापित किया जा सके।

गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का विकास करना होना चाहिए जो उत्कृष्ट, विचारशील और अच्छी रचनात्मक प्रवृत्ति के हों। विशेषकर छात्राओं के संदर्भ में तो यह और भी प्रासंगिक हो जाता है। यह एक व्यक्ति को रुचि के एक या एक से अधिक विशिष्ट विषय जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, भाषा, व्यक्तिगत तकनीकी एवं व्यावसायिक विषयों सहित अन्य क्षेत्रों में गहराई से अध्ययन करने और उत्तम चरित्र, नैतिकता तथा सामाजिक मूल्यों,बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मकता तथा सेवा भावना और 21वीं सदी के कौशल को आवश्यक सीमा तक विकसित करने में सक्षम बनाती है। इन सामाजिक मूल्यों का विकास उच्च शिक्षित छात्राओं के संदर्भ में तो और भी प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि जब तक देश की आधी आबादी के अंदर इस प्रकार से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो जाता तब तक विकसित भारत की कल्पना करना ही व्यर्थ है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कुछ मौलिक परिवर्तन लाती है और इसमें मुख्य आकर्षण बहु– विषयक विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं जिसमें प्रत्येक जिले में या उसके पास कम से कम एक समान पाठ्यक्रम, बेहतर छात्र अनुभव के लिए मूल्यांकन और समर्थन एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान शामिल है। नेशनल रिसर्च फाऊंडेशन विश्वविद्यालय और कॉलेजों में उत्कृष्ट सहकर्मी – समीक्षा कार्य और प्रभावी ढंग से उनके क्रियान्वयन का समर्थन करती है। यह शिक्षा नीति पांच स्तंभों पर केंद्रित है : वहनीयता, अभिगम्यता, गुणवत्ता, न्यायपरस्ता, और जवाबदेही – निरंतर सीखने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए। इसे समाज और अर्थव्यवस्था में ज्ञान की मांग के रूप में नागरिकों की जरूरत के अनुरूप तैयार किया गया है जिससे नियमित आधार पर नए कौशल हासिल करने की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। इस तरह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसर पैदा करना संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 2030 में सूचीबद्ध पूर्ण और उत्पादक रोजगार एवं अच्छे काम की ओर अग्रसर होना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में महत्वपूर्ण सुधारो की मांग करती है। साथ ही साथ अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार करती है जिससे वह नए डिजिटल युग में प्रतिस्पर्धा कर सकें। इस प्रकार नई शिक्षा नीति बहु– विषयकता, डिजिटल साक्षरता, लिखित संचार, समस्या – समाधान, तार्किक तर्क और व्यावसायिक प्रदर्शन पर अत्यधिक प्रभाव डालती है।

अध्ययन का उद्देश्य–

इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षित छात्रों के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। साथ ही साथ नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित प्राथमिक और माध्यमिक डेटा का विश्लेषण करना है। इसके अन्य मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उच्च शिक्षित छात्राओं पर पड़े प्रभावों को विश्लेषित करना है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उच्च शिक्षा के संदर्भ में प्रभाव विस्तार का वर्णन करना है।

उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि को दर्शित करना है।

डेटा संग्रह –

प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से आंकड़ों का संकलन किया गया है जिसके आधार पर संपूर्ण प्रपत्र का विश्लेषण किया गया है।

प्राथमिक स्रोत –

प्राथमिक संसाधन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल पाठ से एकत्र किए गए हैं जो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है।

द्वितीयक स्रोत –

द्वितीयक स्रोत के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर संदर्भित पुस्तकों सहित पुरानी या गैर – मूल जानकारी को आधार बनाया गया है। द्वितीयक स्रोतों में जीवनी, लेखक के कार्यों के महत्वपूर्ण अध्ययन, शोध पत्र और शोध प्रबंध, शोध पुस्तकें, विकिपीडिया ब्रिटानिका एवं अन्य वेबसाइटें शामिल हैं।

अध्ययन का महत्व –

वास्तविक तथ्यों पर आधारित इस अध्ययन के निष्कर्ष समाज के हित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस अध्ययन क्षेत्र में पूर्व अनुसंधान की कमी के कारण यह शोध मॉडल इस अध्ययन के लिए प्रस्तावित है। शोधार्थी में वर्तमान अध्ययन के सभी पहलुओं को समझाने का प्रयास किया है। प्रस्तुत शोध उच्च शिक्षित छात्राओं के संदर्भ में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी पहलुओं को समझाने का स्पष्ट प्रयास किया है। इससे प्रस्तुत अध्ययन, उच्च शिक्षित छात्राओं पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का किस प्रकार प्रभाव पड़ा है, इसको जानने के लिए पाठकों के बीच जागरूकता पैदा करने का प्रयास करेगा। साथ ही साथ यह संदर्भ सामग्री भी तैयार करेगा और आगे के अध्ययन के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।

निष्कर्ष –

अंत में संपूर्ण प्रपत्र के अध्ययन करने के पश्चात यह कहा जा सकता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा रटने वाले विषयों, समय सीमा को पूरा करने और अंक प्राप्त करने से कहीं अधिक है। लेकिन शिक्षा का वास्तविक अर्थ ज्ञान कौशल मूल्यों को प्राप्त करना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधानों को देखते हुए सहज ही कहा जा सकता है कि यह शिक्षा नीति महिलाओं के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। लिंग – समावेशी कोष राज्य के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा जिससे उनको महिलाओं के लिए योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों आदि को लागू करने में सहायता मिलेगी। जैसे महिलाओं के लिए शिक्षण परिसर में पृथक शौचालय स्थापित करना, स्वच्छता संबंधित अन्य सुविधाएं प्रदान करना, स्कूल आने – जाने हेतु मुक्त साइकिल अथवा स्कूटी उपलब्ध करवाना, छात्राओं द्वारा शुल्क जमा करने में असमर्थता की स्थिति में अभिभावकों को सशक्त नगद हस्तांतरण करना ताकि निर्धनता के कारण उन्हें कॉलेज न छोड़ना पड़े।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस तथ्य को भी ध्यान में रखा गया है कि सामाजिक – आर्थिक रूप से पिछड़े समूह जिसमें आधी संख्या महिलाओं की है इसलिए एसईडीजी वर्ग के लिए भी योजनाएं और नीतियां इस शिक्षा नीति में प्रस्तावित की गई हैं, जिससे उनमें विशेष रूप से इन समूह की महिलाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में और भी कई ऐसे प्रावधान है जिससे महिला शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। नीति में लचीलेपन से महिलाओं में शिक्षा के प्रति जिज्ञासा एवं रुझान बढ़ेगा। इससे समाज में अधिक संख्या में महिलाएं शिक्षित होंगी। शिक्षित महिलाएं

अपने कर्तव्यों के साथ अधिकारों के प्रति जागरूक होकर एक सशक्त महिला बनेंगी। अतः यह महिला सशक्तिकरण के लिए एक प्रमुखतम कदम है।

सुझाव –प्रमुख सुझाव निम्न है।

1– छात्राओं के प्रति हिंसा और अपराध को देखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए और अधिक प्रभावी कदम उठाए जाएं ताकि विद्यालय में छात्राओं का पंजीयन बढ़े।

2 – महिलाओं के प्रति सामाजिक मापदंडों का पुनः मूल्यांकन किया जाए एवं उन्हें भी पुरुषों के समान अधिकार दिए जाएं ताकि वह स्वतंत्र निर्णय ले सकें।

3 – घरेलू कार्यों की प्राथमिकता की सामाजिक सोच को बदलकर महिलाओं को शिक्षा मंदिर तक पहुंचाने की प्रभावी योजनाएं क्रियान्वित की जाएं।

4 – शिक्षा के सभी क्षेत्रों में लिंग – संतुलन को बढ़ावा दिया जाए।

5 – सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं की शिक्षा पर तुलनात्मक रूप में अधिक ध्यान केंद्रित किया जाए।

6 – सभी शिक्षण संस्थानों में महिला सुरक्षा, भेदभाव अथवा उत्पीड़न नियमों को शक्ति से लागू किया जाए।

संदर्भ सूची–

1– सिंह अविनाश कुमार, नए भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 2021

2 – जे. कृष्णमूर्ति, शिक्षा क्या है (विनय कुमार वैद्य द्वारा अनुवादित) राजपाल एंड संस दिल्ली, 2020

3– राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार, नई दिल्ली

4 – शर्मा, रामनाथ, राजेंद्र कुमार : सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण, अटलांटिक पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, 1996

5 – शर्मा दीपक, भारतीय शिक्षा के मूल, मै. बुक डिपो, जालंधर पंजाब, 1998